

अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलें, इरादे नहीं।
- अज्ञात



बेरोजगारी ही सबसे बड़ी चुनौती

सर्वेक्षण का संदेश साफ है कि बेरोजगारी ही भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसे इस समस्या को अपने अर्जेंडे पर सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार इस पर भारी असमंजस में दिखती है।

अनुप जोशी

बेरोजगारी दूर न होने से देश के लोगों में चिंता बढ़ रही है। खासकर शहर के लोग बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। शुक्रवार को जारी मार्केट रिसर्च कंपनी 'इप्सॉस' की रिपोर्ट 'वॉट वरीज द वर्ल्ड' के अनुसार 46 फीसदी शहरी भारतीय बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे बड़ी चिंता मानते हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 3 प्रतिशत शहरी भारतीयों की फिक्र बेरोजगारी को लेकर बढ़ गई। दरअसल इप्सॉस हर महीने 28 देशों में यह सर्वे कराती है, जिसका मकसद लोगों की संतुष्टि और असंतुष्टि का स्तर जानना हुआ करता है। इस सर्वे में हमारे लिए एक बात जरूर आश्चर्य करने वाली है कि 69 फीसदी शहरी भारतीय मानते हैं कि देश सही रास्ते पर जा रहा है। मतलब यह कि वे देश की वर्तमान हालत से संतुष्ट हैं। उन्हें वित्तीय और राजनीतिक

भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा, गरीबी, सामाजिक असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे परेशान कर रहे हैं, मगर वे कुल मिलाकर आशावादी हैं। सर्वेक्षण का संदेश साफ है कि बेरोजगारी ही भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसे इस समस्या को अपने अर्जेंडे पर सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार इस पर भारी असमंजस में दिखती है। एक तरफ खुद श्रम मंत्रालय बताता है कि देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी रही जो 45 साल में सबसे ज्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ कई अवसरों पर सरकार के नुमाइंदे इसे नकारते भी रहते हैं। पिछले दिनों श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में इस बात से ही इनकार किया कि रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। जबकि

कई स्रोतों से यह बात सामने आई है कि देश में आर्थिक सुस्ती के कारण बीते कुछ महीनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 लाख से अधिक नौकरियां चली गई हैं। टेक्स्टाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में भी नौकरियां कम हुई हैं। आज ज्यादातर विदेशी या भारतीय कंपनियां कौशल पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं, लेकिन कुशल लोगों की अब भी भारी कमी है। पिछले कुछ वर्षों में उन युवाओं की भारी फौज देश में तैयार हो गई है, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्री हासिल की है, लेकिन उनमें वैसे किसी कौशल का अभाव है, जो उन्हें कोई काम दिला

सके। ऐसे करीब 47 फीसदी शिक्षित युवा हैं, जो किसी भी नौकरी के लायक नहीं। कौशल उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गई योजना स्किल इंडिया का लाभ बड़े पैमाने पर अभी भी नहीं पहुंच पाया है। रोजगार उपलब्ध कराने में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है, पर हमारे देश में इस सेक्टर की बजाय सर्विस सेक्टर का ज्यादा विकास हुआ है, जिनमें रोजगार की गुंजाइश कम है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि उद्योगपति श्रम उन्मुख उत्पादों के क्षेत्र में आगे आ सकें। पर यह सब तभी हो सकेगा जब सरकार रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य को अपने अर्जेंडे में सबसे ऊपर रखे।



तमस और रजस

सुंदरचंद ठाकुर।

हम क्रोध से लाख बचने की कोशिश करें, बच नहीं सकते, क्योंकि क्रोध हमारे भीतर अनिवार्य रहता ही है। वह जीवन के बुनियादी मनोभावों में से एक

धर्म-दर्शन



है, इसलिए हम चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। हम क्रोध को रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन उससे छूट नहीं पा सकते। यह समझना जरूरी है कि प्रकृति के तीन बुनियादी गुण हैं, जिनकी बदौलत यह जगत चल रहा है वृत्त, रजस और तमस। गीता के चौदहवें अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रकृति के इन तीनों गुणों के बारे में बताते हैं। इन गुणों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि तभी हमें मालूम चलेगा कि लोग अलग-अलग तरह की गतिविधियों में क्यों लिप्त हैं। कोई हत्याएं कर रहा है, बलात्कारी है, कोई बिजनेसमें है और अपने व्यापार को बढ़ाता जा रहा है और कोई विवेकानंद की तरह लोगों की मानसिक चेतना को जगाने में संलग्न है।

संपादकीय

दुनियाभर के सत्ताधारी

दुनियाभर के सत्ताधारी अपनी उपलब्धियों का चाहे जितना बखान करें, सच यह है कि आम आदमी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके बजाय रोज नई-नई समस्याएं उसके सामने खड़ी होती जा रही हैं। बहुराष्ट्रीय मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के सर्वेक्षण 'वॉट वरीज दि वर्ल्ड ग्लोबल सर्वे' से पता चलता है कि विभिन्न देशों की जनता की अलग-अलग चिंताएं हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है तो यहां बीते मार्च में किए गए सर्वे में ज्यादातर लोगों ने यह तो माना कि सरकार की नीतियां सही दिशा में हैं लेकिन आतंकवाद की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा सता रही थी। उसके बाद देश के लोग बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान पाए गए।

हालांकि आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की चिंता भी उन्हें परेशान किए हुए है। बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण 28 मुल्कों के औसतन 58 प्रतिशत नागरिकों ने माना है कि उनका देश नीतियों के मामले में भटक-सा गया है। ऐसा सोचने वालों में सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, तुर्की और बेल्जियम के लोग हैं। आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक असमानता ज्यादातर मुल्कों में बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी, अपराध, हिंसा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता इनके बाद ही आती है। अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास चीन के लोगों का है। वहां दस में नौ लोग अपनी सरकारी नीतियों की दिशा सही मानते हैं। यह ऑनलाइन सर्वे 28 देशों के 65 वर्ष से कम आयु के लोगों के बीच प्रायः हर महीने किया जाता है। जैसे भारत में इस बार का सर्वे पुलवामा हमले के बाद किया गया तो इस पर उस हादसे की छाया थी लेकिन देश के पिछले सर्वेक्षणों को देखें तो आतंकवाद का स्थान यहां की चिंताओं में नीचे रहा है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखी जाती रही है।

साफ है कि अब गढ़वाली परिवारों के युवा प्रायः सरकारी नौकरी नहीं करते। इसलिए मिंटो रोड से शिफ्ट कर गए गढ़वाली परिवार। दरअसल 1930 के आसपास गढ़वाल से लोगों ने दिल्ली का रुख करना शुरू किया था।

लेकिन सियासी तपिश बढ़ेगी

विवेक शुक्ला

मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते पारा थोड़ा और नीचे जा सकता है, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। लेकिन फिलवक्त देश का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि सर्दी कितनी ही कड़ाके की पड़े, इस पूरे हफ्ते सियासी तपिश पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जाएगी। इस हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी भी नागरिकता कानून और एनआरसी पर उठे विवाद को जल्द से जल्द समाप्त कर आगे बढ़ना चाहेगी। अब बीजेपी इस विवाद से बाहर निकलने को हाथ-पैर चलाने लगी है और पांच जनवरी से सीए और एनआरसी पर जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान में पार्टी ने 3 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। एक महीने पहले महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी जिसके तहत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम बने। अब इस सरकार के लिए पहली परीक्षा इसी हफ्ते होगी। उद्धव सरकार में पहला कैबिनेट विस्तार होगा। जहां एनसीपी की नजर इस फेरबदल में डिप्टी सीएम पद पर है, वहीं कांग्रेस को मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय चाहिए। शिवसेना को राजनीतिक रूप से यह संदेश देना है कि



सरकार बनाने की कोशिश में उसकी स्थिति बेबस और कमजोर वाली नहीं हुई है। बीजेपी तीनों दलों के अंतर्विरोध का अधिकतम सियासी लाभ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। इसका संकेत पिछले दिनों ही दिख गया जब राहुल गांधी ने दिल्ली की रैली में सावरकर पर टिप्पणी की तो तुरंत बीजेपी ने मुंबई में उसे मुद्दा बना दिया और कांग्रेस और शिवसेना के बीच हल्की-फुल्की जुबानी जंग भी हुई। जानकारों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार से यह संदेश जाएगा कि सरकार पर किसका नियंत्रण अधिक है। ऐसे में तीनों दल इसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने फेरबदल से पहले ही बयान भी दे दिया है कि अब तक तक उन्हें जो मंत्रालय

मिले हैं, वह उनके हिसाब से कम हैं। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार की मंत्रिमंडल में बतौर डिप्टी सीएम वापस होगी या नहीं, इसका भी खुलासा इसी विस्तार में हो जाएगा। अगर अजित पवार डिप्टी सीएम बनते हैं तो राज्य में सत्ता के दो केंद्र बन सकते हैं। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र के लिए अगला हफ्ता बेहद अहम है और नई सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसके अलावा अगले साल होने वाली सबसे बड़ी सियासी जंग का भी बिगुल बज सकता है। पूरी संभावना बताई जा रही है कि अगले हफ्ते चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर सकता है। अगले साल पूरे देश में दिल्ली के अलावा सिर्फ बिहार में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी करना चाहेगी तो अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी बार दिल्ली चुनाव जीतकर अपनी छाप भी जरूर छोड़ना चाहेंगे। दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा चुनाव परिणाम का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ने की पूरी उम्मीद है। अगर अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी बार जीतते हैं तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में आने की हसरत फिर से जग सकती है। चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार के रूप में जोड़कर आम आदमी पार्टी ने इसका संकेत भी दे दिया है।

सूडूकु नववाला-5198				*****			
3		8				9	
	8	6		9	5		
6	5		4			7	1
	4					2	
1	2		6			9	8
		6	4		5	8	
9			1				7

अपना ब्लॉग

खुदाई में अपन की पीएचडी है भाय! प्रभुनाथ शुक्ला। खुदाई हमारी संस्कार में रची बसी है। हमारे पुरखों की यह विरासत रही है। खुदाई की वजह से हमने ऐतिहासिक सभ्यताएं हासिल की हैं, जिनका महत्व हमारी इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में दर्ज है। खुदाई से निकली ऐसी सभ्यताओं पर हमें गर्व है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ मेसोपोटामियां जैसी संस्कृति खुदाई से निकली सभ्यताएं हैं। जिस मुल्क में अपन रहते हैं वहां खुदाई हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। खुदाई यहां की एक कला और संस्कृति है। खुदाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पुल, रेल, सड़कें, बांध, अवास, अंडरब्रिज, कालोनियां, सीवर यह सब खुदाई से निकली बुलंदियां हैं। अब आप सोचिए! खुदाई बंद हो जाए तो विकास का पहिया जाम हो जाएगा। सभ्यताएं विलुप्त हो जाएंगी। टेंशन बढ़ाने वाले डिटेंशन कहां से आएंगे। खुदाई हमारी सोच यानी न्यू इंडिया की ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको मालूम है खुदाई से ही गड़े मुर्दे उखाड़ने का मुहावरा निकला है। खुदाई और खोज एक दूसरे से जुड़े हैं। खुदाई हमारे बाप-दादाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है।

